Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding laying of Barwadih-Chirmiri railway line - Laid

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): झारखण्ड के चतरा लोक सभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व बरवाडीह-चिरमिरी रेलवे लाइन परियोजना प्रस्तावित थी जिसमें चिरमिरी से अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन बन चुकी है। बरवाडीह से अम्बिकापुर तक रेलवे लाइन का निर्माण लंबित है। इस परियोजना के लिए आजादी से पूर्व में ही भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। अधूरा निर्माण कार्य भी हुआ है। यह परियोजना झारखंड के पलामू संभाग को छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से जोड़ता है। जनजातीय बाहुल्य सरगुजा एवं झारखंड का क्षेत्र सीधे मुंबई, हावड़ा से जुड़ता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग से मुंबई-कोलकाता की दूरी 400 किलोमीटर कम हो जाएगी।

182 किलोमीटर इस रेल लाइन के लिए 2007 में सर्वे रिपोर्ट करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था जो वर्ष 2013-14 के बजट में 1137 करोड़ रुपए हो गया जिसमें से वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में मात्र 10-10 लाख रुपए बजट आवंटित किया गया है। इस कार्य पूर्ण होने के लिए 1136.80 लाख रुपए की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्य सरकारों एवं कोल इंडिया के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करना है। मेरा सरकार के माध्यम से रेल एवं कोयला मंत्री जी से आग्रह है कि आजादी से पूर्व की प्रस्तावित लाइन बरवाडीह-चिरमिरी प्रस्तावित रेल लाइन को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाये जायें। झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं कोल इंडिया के साथ परियोजना पर विस्तृत चर्चा कर पूर्ण करने के लिए समय-सीमा तय की जाये। साथ ही एक अन्य रेल परियोजना के पूर्ण होने से रेलवे से अछूते रहे चतरा जिले का सम्पर्क पूरे देश से हो सकेगा। चतरा-गया (97 कि.मी.) रेल लाइन के माध्यम से चतरा को रेलवे से जोड़ने की मांग बहुत पुरानी है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट में स्वीकृत चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2008-09 में 416 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया था। चतरा जिले में 37.672 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। मार्च, 2017 तक 31 करोड़ रुपए इस लाइन के लिए खर्च किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ रुपए परिव्यय प्रदान किया गया है। परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 4543 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से जहां खनिज संपदा का परिवहन अत्यंत तीव्र गति से हो पायेगा, वहीं आवागमन की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र की भी उन्नति होगी। उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की संभावना प्रबल हो सकेगी।